


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 171]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम 2015

मि. सं. 91-1/2013 (टी. एफ. जी. एस.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) जैसे संवत अधिनियम के अनुच्छेद 20 के उप-अनुच्छेद (1) से संयुक्त रूप से पढ़ा जाए उस अधिनियम 26 के अनुच्छेद (1) की धारा (जी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम निर्मित कर रहा है, नामतः :-

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं समासः— (1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इसमें सुधार) विनियम, 2015 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम भारत वर्ष में सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों पर लागू होंगे।
- (3) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से ये लागू माने जाएंगे।
2. परिभाषाएँ— इन विनियमों में—वर्षाते विषयवस्तु के अन्तर्गत कुछ अन्यथा जरूरी है—
- (अ) "पंडित महिला" से अर्थ है किसी भी आयु वर्ग की एक ऐसी महिला—चाहे वह रोजगार में है या नहीं, किसी कार्य स्थल में कथित तौर से प्रतिवादी द्वारा कोई लैंगिक प्रताड़ना के कार्य का शिकार बनी है,
- (ब) "अधिनियम" से अर्थ है कार्य स्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 (2013 का 14);
- (स) "परिशर" का अर्थ उस स्थान अथवा भूमि से है जहाँ पर उच्चतर शैक्षिक संस्थान तथा इतरकी संयुक्त संस्थागत सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, लेक्चर हॉल, आवास, हॉल, शौचालय, छात्र केंद्र, छात्रावास, भोजन कक्षों, स्टेडियम, वाहन पार्क रखल, उपवनों जैसे स्थल तथा अन्य कुछ सुविधाएँ जैसे स्वास्थ्य केंद्र, कैंटीन, बैंक पटल इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें छात्रों द्वारा उच्चशिक्षा के छात्र के रूप में दीक्षा लिया जाता हो—जिस में वह परिवहन शामिल है जो उन्हें उस संस्थान से आने जाने के लिए, उस संस्थान के अलावा क्षेत्रीय भ्रमण हेतु

- (६) शारीरिक रूप से सवध बनाना अथवा पास बने रहने की कोशिश करना
- (७) अस्वील साहित्य दिखाना
- (11) निम्न परिस्थितियों में से किसी एक में (अथवा इससे अधिक एक या सभी में) यदि ऐसा पाया जाता है अथवा वह ऐसे किसी यत्न के बारे में है या उससे संबंधित है जिसमें व्यापक रूप से या छिपे रूप में लैंगिक संकेत छिपे हैं—
- (अ) छिपे तौर से या प्रत्यक्ष रूप से अधिमान्य व्यवहार देने का वायदा जो लैंगिक समर्थन के एवज में है;
- (ब) कार्य के निष्पादन में छिपे रूप से या सीधे तौर से रुकावट डालने की धमकी,
- (स) संबद्ध व्यक्ति के वर्तमान अथवा उसके भविष्य के प्रति छिपे तौर से या सीधे तौर से धमकी देकर,
- (द) एक दृष्टत भरा हिंसात्मक या ड्रैपपूर्ण वातावरण पैदा करके,
- (३) ऐसा व्यवहार करना जो कि संबद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य उसकी सुरक्षा, प्रतिष्ठा अथवा उसकी शारीरिक दृढ़ता को दुष्प्रभावित करने वाला है;
- (एल) "छात्र" शब्द का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जिसे विधिवत प्रवेश मिला हुआ है, जो नियमित रूप से या दूर शिक्षा विधि से एक उच्च शिक्षा संस्थान में, एक अध्ययन पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहा है जिसमें बाधु अथवा अधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है:
- यद्यपि, ऐसे किसी छात्र के साथ यदि कोई लैंगिक उत्पीड़न की घटना होती है जो उच्च शिक्षा संस्थान परिसर में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में है— यद्यपि वह प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ है तो इन विनियमों के आधार पर उस छात्र को उच्च शिक्षा संस्थान का छात्र माना जाएगा:
- यद्यपि एक ऐसा छात्र जो किसी उच्चतर शैक्षिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त है तथा उस संस्थान में भागीदार है और उस छात्र के प्रति कोई लैंगिक उत्पीड़न होता है तो उसे उस उच्च संस्थान का छात्र माना जाएगा,
- (एम) "किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न" उस रिश्ते को दर्शाता है जब लैंगिक उत्पीड़न की घटना किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा या किसी वाहक के आदमी द्वारा की गई हो जो ना तो उस उच्च शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी अथवा उसका छात्र है—बल्कि उस संस्थान में एक आगन्तुक है जो अपने अन्य किसी कान या उद्देश्य से आया हुआ है;
- (एन) "उत्पीड़न" का अर्थ है किसी व्यक्ति से नकारात्मक व्यवहार जिसमें छिपे तौर से या सीधे तौर से लैंगिक दुर्भावना की नीगत छिपी होती है;
- (ओ) "कार्यस्थल" का अर्थ है उच्चतर शैक्षिक संस्थान का परिसर जिसमें शामिल हैं:
- (अ) कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठा, उद्योग, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा एकत्र जो उपयुक्त उच्चतर शैक्षिक संस्थान द्वारा पूरी तरह अथवा पर्याप्त रूप से उपलब्ध निधि द्वारा सीधे तौर से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित, स्वामित्व वाले या उससे नियन्त्रित है;
- (ब) ऐसा कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर या प्रतियोगिता या खेलकूद क्षेत्र चाहे वह आवासीय है या नहीं या उसे उच्चतर शैक्षिक संस्थान की प्रशिक्षण, खेलकूद अथवा अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है;
- (स) ऐसा कोई स्थान जिसमें कर्मचारी अथवा छात्र अपने रोजगार के दौरान या अध्ययन के दौरान आते रहते हैं तथा जिस गतिविधि में यातायात शामिल है जिसे कार्यकारी प्राधिकारी ने ऐसे भ्रमण के लिए उपलब्ध कराया है जो उस उच्च शैक्षिक संस्थान में अध्ययन के लिए हैं।

3. उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के दायित्व—(1) प्रत्येक उच्चतर शैक्षिक संस्थान)

- (अ) कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण एवं निषेध संबंधी अपनी नीति एवं विनियमों में उपरोक्त परिभाषाओं की भावना को यथा आवश्यक उपयुक्त रूप में सम्मिलित करें तथा इन विनियमों की आवश्यकता अनुसार अपने अध्यादेशों एवं नियमों को संशोधित करना;
- (ब) लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध प्रावधानों को अधिसूचित करना तथा उनके विरुद्ध प्रचार-प्रसार का सुनिश्चित करना;

जाएगा—व्यक्ति, न्यायालय के निर्णय एवं अन्य कानून तथा नियमों द्वारा उस कानूनी ढोंच में लगभग संसाधन प्राप्त रहेंगे जिनके अनुसार अधिनियम लागू किया जाना है.

- (2) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों का कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा अधिदेशात्मक रूप से पूरा समर्थन किया जाना चाहिए तथा यह देखा जाना चाहिए कि आई.सी.सी. की सिफारिशों का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा रहा है कि नहीं। आई.सी.सी. के प्रकाश के लिए समस्त संभावित संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए— जिनमें कार्यालय और भवन अवसंरचना सहित (कम्प्यूटर, फोटो कॉपीयर, श्रव्य दृश्य उपकरण आदि) स्टाफ (टाइपिस्ट, सलाह एवं कानूनी सेवाओं) सहित पर्याप्त रूप में वित्तीय संसाधन का आवंटन भी हो.
- (3) असुरक्षित, दुर्बल वर्ग विशेष रूप से प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं और उनके द्वारा शिकायत करना और भी ज्यादा कठिन होता है। क्षेत्र, वर्ग, जाति, लैंगिक प्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पहचान, एवं पृष्ठक रूप से सम्बन्ध से असुरक्षा सामाजिक रूप से संयोजित हो सकती है। समर्थकारी समितियों को इस प्रकार की असुरक्षितताओं के प्रति अति संवेदनशीलता एवं विशेष जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है.
- (4) वार्षिक शोध छात्र और डॉक्टरल छात्र विशेष रूप से आक्रामक होते हैं, अतः उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाए कि शोध सर्वेक्षण की नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश उचित रूप से लागू हो रहे हैं.
- (5) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा उनकी लैंगिक उत्पीड़न विरोधी नीति की क्षमता का नियमित रूप से आंशिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए.
- (6) सभी अकादमिक स्टाफ कॉलेजों (जिन्हें अब मानव संसाधन विकास केन्द्रों के रूप में गाया जाता है) (एधआरडीसी) और क्षमता निर्माण के क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा लैंगिक संबंधी सत्रों को अपने अभिमुखी एवं पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों में निगमित करना चाहिए। अन्य सब विषयों से भी इसे प्राथमिकता दी जाए तथा इसी मुख्य धारा के रूप में विशेष रूप से बनाया जाए तथा इसके लिए "यूजीसी सक्षम" रिपोर्ट का उपयोग करें जिसमें, इस बारे में, प्रविष्टियों उपलब्ध कराई जाती हैं.
- (7) उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रशासकों के लिए संचालित अभिमुखी पाठ्यक्रमों में आवश्यक रूप से लैंगिक संवेदीकरण तथा लैंगिक उत्पीड़न की समस्याओं पर एक मापदण्ड होना चाहिए। उच्चतर शैक्षिक संस्थान के समस्त विभागों में मौजूद सदस्यों के लिए कार्यशालाएँ नियमित रूप से संचालित की जानी चाहिए.
- (8) समस्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं को संस्थानों के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए और इसके लिए सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक परामर्शदाता होने चाहिए.
- (9) कई उच्चतर शैक्षिक संस्थान जिनके विशाल परिसर हैं जिनमें प्रकाश संबंधी व्यवस्था बहुत अदृश है तथा अन्य संस्थानों के लोगों के अनुभव अनुसार वे स्थान असुरक्षित समझे जाते हैं, वहाँ पर्याप्त प्रकार की व्यवस्था अवसंरचना एवं रख-रखाव का एक अनिवार्य अंग है.
- (10) पर्याप्त एवं अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुरक्षा स्टाफ आवश्यक रूप से होना चाहिए जिसमें महिला सुरक्षा स्टाफ सदस्य अच्छी संख्या में हों, जिससे संतुलन बना रहे। सुरक्षा स्टाफ नियुक्ति के मामले में लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को एक शर्त के रूप में माना जाना चाहिए.
- (11) उच्चतर शैक्षिक संस्थान आवश्यक रूप से विश्वस्तनीय जन यातायात को सुनिश्चित करें— विशेष रूप से उच्चतर शैक्षिक संस्थानों के विस्तृत परिसरों के अन्दर विभिन्न विभागों के मध्य जैसे— छात्रावासों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं तथा मुख्यालय और विशेष रूप से वे स्थान जिन तक पहुँच पाना दैनिक शैक्षिकताओं के लिए कठिन है। सुरक्षा की कमी तथा उत्पीड़न बहुत बड़ा जाता है जब कर्मचारी और छात्र सुरक्षित जन यातायात पर निर्भर नहीं रहते हैं। कर्मचारी एवं छात्रों द्वारा पुरतकालता और प्रयोगशालाओं में देर रात तक काम करने और शान के समय अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा भरोसेमंद यातायात का प्रबंध किया जाना चाहिए.
- (12) आवश्यक उच्चतर शैक्षिक संस्थानों द्वारा महिला छात्रावासों की संरचना को प्राथमिकता दी जाए। महिला छात्रावास, जो सभी प्रकार के उत्पीड़न से थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रदान करते हैं, उस उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा इच्छुक युवा महिलाओं के लिए अत्यन्त जरूरी है.

- (4) आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि तीन वर्ष की होगी। उच्चतर शैक्षिक संस्थान ऐसी एक प्रणाली का उपयोग करें जिसके द्वारा आन्तरिक शिकायत केंद्र के सदस्य का एक रिहाई भाग प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहे।
- (5) आन्तरिक समिति को बैठक आयोजित करने के लिए जो सदस्य गैर सरकारी संगठनों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं उन्हें कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसे शुल्क अथवा भत्ते का भुगतान किया जाए, जैसा निर्धारित किया गया है।
- (6) जिस स्थिति में आन्तरिक समिति का अध्यक्ष अधिकारी अथवा इसका कोई सदस्य यदि:-

- (अ) अधिशिगम की धारा 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, अथवा
- (ब) वह किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है अथवा उसके विरुद्ध वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी अपराध के बारे में कोई पड़ताल लम्बित है, अथवा
- (स) किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत वह दोषी पाया गया है अथवा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित है, अथवा
- (द) उसने अपने पद का दुरुपयोग इस सीमा तक किया है कि कार्यालय में उसकी संवामें निरन्तरता को जनहित के प्रतिकूल माना जाएगा,

तो ऐसा अध्यक्ष अधिकारी अथवा सदस्य, यथास्थिति, इस समिति से हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार से होने वाली रिक्ति अथवा ऐसी कोई वैगितिक (केजुअल) रिक्ति को नये भाग्यक्रम द्वारा इस धारा के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा;"

5. आन्तरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) :- आन्तरिक शिकायत समिति करेगी :-

- (अ) यदि कोई कर्मचारी अथवा छात्र पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज करना चाहता है तो उसे सहायता उपलब्ध कराएगी;
- (ब) विवाद समाधान के हेतु बातचीत संबंधी तन्त्र उपलब्ध कराना ताकि विवादित बातों पर पूर्वानुमान को समीचीन एवं उचित मैत्रीपूर्ण क्रिया द्वारा देखा जा सका जिससे उस शिकायतकर्ता के अधिकारों की हानि न हो तथा जिससे पूरी तरह से दण्डात्मक दृष्टिकोणों की न्यूनतम जरूरत हो जिनसे और अधिक जानकारी, विमुखता अथवा हिंसा न बढ़े;
- (स) उस व्यक्ति की पहचान उजागर किये बिना उस शिकायतकर्ता की सुरक्षा बनाए रखना तथा रचीकृत अवकाश अथवा उपस्थिति संबंधी अनिवार्यताओं में छूट द्वारा अथवा अन्य किसी विभाग में अथवा किसी सर्वेक्षणकर्ता के पास स्थानान्तरण द्वारा, तथा आवश्यक रूप से इस शिकायत के लम्बित होने की अवधि में अथवा उस अपराधकर्ता के स्थानान्तरण का भी प्रावधान किया जाएगा;
- (द) तैगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निपटान करते समय सुनिश्चित करे कि पीड़ित व्यक्ति या गवाहों का शोषण ना किया जाए अथवा उनके साथ भेदभाव न किया जाए, तथा
- (ई) किसी भी आपृत व्यक्ति के विरुद्ध अथवा प्रतिकूल कार्यवाई पर प्रभाव को सुनिश्चित करना क्योंकि यह कर्मचारी अथवा छात्र एक संरक्षित गतिविधि में व्यस्त है;

6. शिकायत करने एवं जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:- आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी शिकायत को दायर करने और उस शिकायत की जाँच करने के लिए इन विनियमों और अधिनियम में निर्धारित प्रणाली का अनुपालन करेगी ताकि वह समयबद्ध रूप से पूरी हो सके। उच्चतर शैक्षिक संस्थान, आन्तरिक शिकायत समिति को सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा ताकि जाँच पड़ताल शीघ्रता से संचालित हो सके तथा आवश्यक गोपनीयता भी बनी रहे;

7. तैगिक उत्पीड़न की शिकायत दायर करने की प्रक्रिया :- किसी भी अराजतुष्ट व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह घटना होने की तिथि से तीन माह के भीतर लिखित शिकायत आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत करे और यदि लगातार कई घटनाएँ हुई हो तो सबसे बाद की घटना से तीन माह के भीतर उसे प्रस्तुत करे;

वर्षात जहाँ ऐसी शिकायत लिखित रूप में नहीं दी जा सकती है, वहाँ अध्यक्ष अधिकारी अथवा आन्तरिक समिति का कोई भी सदस्य, उस व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समस्त सम्भव सहायता प्रदान करेगा;

वर्षात, इसके साथ ही आई.सी.सी लिखित रूप से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर समग सीमा विस्तारित कर सकती है, परन्तु वह तीन माह से अधिक की नहीं होगी, यदि इस बात को आवश्यक किया गया हो कि परिस्थितियों ऐसी थी कि जिनके कारण वह व्यक्ति इस कथित अवधि के दौरान शिकायत दायर करने से वंचित रह गया था;

8. जाँच पड़ताल की प्रक्रिया:-

- (क) एक विषय प्रथम एक परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना;
- (ख) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी।
- (ग) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना,
- (घ) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी धरतली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगा—
- (अ) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुःख पहुँचा है;
- (ब) परतः लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी,
- (ग) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनोरोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;
- (घ) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और
- (ङ) ऐसे समस्त गुणगान का एकगुणित रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य;

11. झूठी शिकायत के विरुद्ध कार्यवाई—

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि लैंगिक उत्पीड़न मामलों में कर्मचारियों एवं छात्रों की सुरक्षा के प्रावधानों का दुरुपयोग न हो, असत्य एवं द्वेष भावना पूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है तथा उन्हें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में प्रचारित प्रसारित किया जाना चाहिए। आन्तरिक शिकायत समिति यदि यह निष्कर्ष निकालती है कि लगाए गए अभियोग असत्य थे, विद्वेषपूर्ण थे अथवा यह जानते हुए भी कि वह शिकायत अराज्य अथवा जाली है अथवा भ्रमक सूचना को उस पड़ताल के दौरान उपलब्ध कराया गया है तो शिकायतकर्ता विनियम (10) के उप विनियम (1) के तहत दण्डित किये जाने के लिए बाध्य होगा यदि शिकायतकर्ता एक कर्मचारी है, तथा यदि वह अपराधकर्ता एक छात्र है तो वह इस विनियम की उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अनुसार सजा के लिए बाध्य होगा तथापि किसी भी शिकायत को प्रमाणित करने अथवा उसके लिए पर्याप्त तथ्य उपलब्ध न कर पाने का आधार शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाई करने का कारण नहीं माना जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दायर शिकायत की जाँच पड़ताल द्वारा तय किया जाना चाहिए तथा इस बारे में किसी कार्यवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व इस विषय में निर्धारित प्रणाली के अनुसार जाँच की जानी चाहिए।

12. गैर अनुपालन के परिणाम—

- (1) ऐसे संस्थान जो जानबूझकर अथवा बारंबार उन दायित्वों तथा कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ बना रहता है जिन्हें कर्मचारियों एवं छात्रों के प्रति लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं सम्मोचन हेतु निर्धारित किया गया है, तो डी.ए. स्थिति में आयोग विधिवत नोटिस देकर निम्न में से किसी एक अथवा इससे अधिक विन्दुओं पर कार्यवाई करेगा—
- (अ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12(सी) के अन्तर्गत की गई घोषणा को वापस लिये जाने के विषय में है, उसका आहरण किया जाना;
- (ब) आयोग द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत अनुरक्षित सूची में से उस विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय का नाम हटाना;
- (ग) संस्थान को आर्टिफिट किसी भी अनुदान को रोक देना;
- (घ) आयोग को किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसी भी सहायता को प्राप्त करने के लिए उस संस्थान को अपात्र घोषित किया जाना;
- (ङ) जन संधारण को, एवं रोजगार अथवा प्रवेश के इच्छुक भावी प्रत्याशियों को एक ऐसे नोटिस द्वारा सूचित करना जो समाचार पत्रों में प्रमुख रूप से दर्शाया गया है अथवा उपयुक्त मीडिया में दर्शाया गया है तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है तथा जिस नोटिस में घोषणा की गई है कि वह संस्थान लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अथवा जवसमतदयम व्यवसयलतद का समर्थन नहीं करता है;
- (च) यदि वह एक महाविद्यालय है तो उसके सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसकी सहसम्बद्धता को आहरित करने की अनुशंसा के लिये कहे;

- (जी) यदि वह एक मानित विश्वविद्यालय संस्थान है तो केन्द्र सरकार को उस मानित विश्वविद्यालय के आहरण की अनुशंसा करना;
- (एच) यदि वह किसी राज्य अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अथवा नियमित विश्वविद्यालय है तो उसके इस स्तर को आहरित करने के लिए उपयुक्त राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (आई) जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाना हो तदनुसार अपने अधिकारों के अनुसार यथोचित रूप से ऐसी समयावधि के लिए दण्ड प्रदान कर सकता है जिस समय तक वह संस्थान इन विनियमों में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है;
- (जे) इन विनियमों के अन्तर्गत आयोग द्वारा उस समय तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि संस्थान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रदत्त सुअवसर के आधार पर उनकी सुनवाई कर ली गई हो;

[विज्ञापन—III/4/असा/53]

जसपाल एस. संधु, सचिव, यूजीसी

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(University Grants Commission)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015

No. F. 91-1/2013(TFGS).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), read with sub-section (1) of Section 20 of the said Act, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) Regulations, 2015.
 - (2) They shall apply to all higher educational institutions in India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "aggrieved woman" means in relation to work place, a woman of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;
 - (b) "Act" means the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013);
 - (c) "campus" means the location or the land on which a Higher Educational Institution and its related institutional facilities like libraries, laboratories, lecture halls, residences, halls, toilets, student centres, hostels, dining halls, stadiums, parking areas, parks-like settings and other amenities like health centres, canteens, Bank counters, etc., are situated and also includes extended campus and covers within its scope places visited as a student of the HEI including transportation provided for the purpose of commuting to and from the institution, the locations outside the institution on field trips, internships, study tours, excursions, short-term placements, places used for camps, cultural festivals, sports meets and such other activities where a person is participating in the capacity of an employee or a student of the HEI;

- (d) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (e) "covered individuals" are persons who have engaged in protected activity such as filing a sexual harassment charge, or who are closely associated with an individual who has engaged in protected activity and such person can be an employee or a fellow student or guardian of the offended person;
- (f) "employee" means a person as defined in the Act and also includes, for the purposes of these Regulations trainee, apprentice (or called by any other name), interns, volunteers, teacher assistants, research assistants, whether employed or not, including those involved in field studies, projects, short-visits and camps;
- (g) "Executive Authority" means the chief executive authority of the HEI, by whatever name called, in which the general administration of the HEI is vested. For public funded institutions the Executive Authority means the Disciplinary Authority as indicated in Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 or its equivalent rules;
- (h) "Higher Educational Institution" (HEI) means a university within the meaning of clause (j) of section 2, a college within the meaning of clause(b) of sub-section (1) of section 12A and an institution deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
- (i) "Internal Complaints Committee" (ICC) means Internal Complaints Committee to be constituted by an HEI under sub regulation (1) of regulation 4 of these regulations. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;
- Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;
- (j) "protected activity" includes reasonable opposition to a practice believed to violate sexual harassment laws on behalf of oneself or others such as participation in sexual harassment proceedings, cooperating with an internal investigation or alleged sexual harassment practices or acting as a witness in an investigation by an outside agency or in litigation;
- (k) "sexual harassment" means-
- (i) "An unwanted conduct with sexual undertones if it occurs or which is persistent and which demeans, humiliates or creates a hostile and intimidating environment or is calculated to induce submission by actual or threatened adverse consequences and includes any one or more or all of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication), namely:-
- (a) any unwelcome physical, verbal or non verbal conduct of sexual nature;
 - (b) demand or request for sexual favours;
 - (c) making sexually coloured remarks
 - (d) physical contact and advances; or
 - (e) showing pornography"
- (ii) any one (or more than one or all) of the following circumstances, if it occurs or is present in relation or connected with any behaviour that has explicit or implicit sexual undertones-
- (a) implied or explicit promise of preferential treatment as quid pro quo for sexual favours;
 - (b) implied or explicit threat of detrimental treatment in the conduct of work;
 - (c) implied or explicit threat about the present or future status of the person concerned;
 - (d) creating an intimidating offensive or hostile learning environment;
 - (e) humiliating treatment likely to affect the health, safety dignity or physical integrity of the person concerned;

harassment, contact details of members of Internal Complaints Committee, complaints procedure and so on. Any existing body already functioning with the same objective (like the Gender Sensitization Committee Against Sexual Harassment (GSCASH)) should be reconstituted as the ICC;

Provided that in the latter case the HEI shall ensure that the constitution of such a Body is as required for ICC under these regulations. Provided further that such a Body shall be bound by the provisions of these regulations;

- (i) inform employees and students of the recourse available to them if they are victims of sexual harassment;
- (j) organise regular orientation or training programmes for the members of the ICC to deal with complaints, steer the process of settlement or conciliation, etc. with sensitivity;
- (k) proactively move to curb all forms of harassment of employees and students whether it is from those in a dominant power or hierarchical relationship within HEIs or owing to intimate partner violence or from peers or from elements outside of the geographical limits of the HEI;
- (l) be responsible to bring those guilty of sexual harassment against its employees and students to book and initiate all proceedings as required by law and also put in place mechanisms and redressal systems like the ICC to curb and prevent sexual harassment on its campus;
- (m) treat sexual harassment as a misconduct under service rules and initiate action for misconduct if the perpetrator is an employee;
- (n) treat sexual harassment as a violation of the disciplinary rules (leading up to rustication and expulsion) if the perpetrator is a student;
- (o) ensure compliance with the provisions of these regulations, including appointment of ICC, within a period of sixty days from the date of publication of these regulations;
- (p) monitor the timely submission of reports by the ICC;
- (q) prepare an annual status report with details on the number of cases filed and their disposal and submit the same to the Commission.

3.2 Supportive measures --(1) The rules, regulations or any such other instrument by which ICC shall function have to be updated and revised from time-to-time, as court judgments and other laws and rules will continue to revise the legal framework within which the Act is to be implemented.

(2) The Executive Authority of the HEIs must mandatorily extend full support to see that the recommendations of the ICC are implemented in a timely manner. All possible institutional resources must be given to the functioning of the ICC, including office and building infrastructure (computers, photocopiers, audio-video, equipment, etc.), staff (typists, counselling and legal services) as, well as a sufficient allocation of financial resources.

(3) Vulnerable groups are particularly prone to harassment and also find it more difficult to complain. Vulnerability can be socially compounded by region, class, caste, sexual orientation, minority identity and by being differently abled. Enabling committees must be sensitive to such vulnerabilities and special needs.

(4) Since research students and doctoral candidates are particularly vulnerable the HEIs must ensure that the guidelines for ethics for Research Supervision are put in place.

(5) All HEIs must conduct a regular and half yearly review of the efficacy and implementation of their anti-sexual harassment policy.

- (a) A Presiding Officer who shall be a woman faculty member employed at a senior level (not below a Professor in case of a university, and not below an Associate Professor or Reader in case of a college) at the educational institution, nominated by the Executive Authority;

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section 2(a),

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organization;”

- (b) two faculty members and two non-teaching employees, preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge, nominated by the Executive Authority;
- (c) Three students, if the matter involves students, who shall be enrolled at the undergraduate, master's, and research scholar levels respectively, elected through transparent democratic procedure;
- (d) one member from amongst non-government organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment, nominated by the Executive Authority.
- (2) At least one-half of the total members of the ICC shall be women.
- (3) Persons in senior administrative positions in the HEI, such as Vice-Chancellor, Pro Vice-Chancellors, Rectors, Registrar, Deans, Heads of Departments, etc., shall not be members of ICCs in order to ensure autonomy of their functioning.
- (4) The term of office of the members of the ICC shall be for a period of three years. HEIs may also employ a system whereby one-third of the members of the ICC may change every year.
- (5) The Member appointed from amongst the non-governmental organizations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the Executive Authority as may be prescribed.
- (6) Where the Presiding Officer or any member of the Internal Committee:
- contravenes the provisions of section 16 of the Act; or
 - has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or
 - he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or
 - has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section.”

5. Responsibilities of Internal Complaints Committee (ICC) - The Internal Complaints Committee shall:
- provide assistance if an employee or a student chooses to file a complaint with the police;

Updated on 04.11.2022

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension
Department of Personnel & Training
Establishment Division

PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT THE WORKPLACE

In the case of Vishaka and Ors Vs State of Rajasthan and Ors (JT 1997 (7) SC 384), the Hon'ble Supreme Court had laid down the guidelines and norms to be observed to prevent sexual harassment of working women. In pursuance to the pronouncement of this judgement, Department of Personnel and Training took the following steps:

- (i) Guidelines/ Norms of the Hon'ble Supreme Court were circulated by Department of Personnel & Training vide OM No. 11013/10/97-Estt.(A) dated 13.02.1998 for strict compliance by the Ministries/ Departments.
- (ii) Amendments in Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 were also carried out by inserting the Rule 3-C declaring Sexual Harassment of Working Women as a misconduct, vide Notification No. 11013/10/97-Estt.(A) dated 13.02.1998 published in Gazette of India as G.S.R. 49 dated 07.03.1998
- (iii) Subsequently, Central Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965 were also amended by inserting a provision below sub-rule 2 of Rule 14 in connection with treatment of the Complaint Committee as Inquiring Authority and to follow the procedure as laid down in these Rules to hold inquiry into the complaints of Sexual Harassment. This was notified vide Notification No. 11012/5/2001-Estt.A dated 01.07.2004 published in Gazette of India vide G.S.R. No. 225 dated 10.07.2004

2. Later on, the 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013' {SHWW (PPR) Act} was promulgated on 22.04.2013. The 'Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013' were notified on 09.12.2013. The Act and the Rules framed thereunder provide a redressal mechanism for handling cases of sexual harassment of women at workplace.

3. Thus, the provisions relating to handling cases of sexual harassment of women at workplace are scattered across SHWW (PPR) Act, Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, etc. In addition, a number of executive instructions covering different aspects of this issue have been issued from time to time. Now, with a view to facilitate the Ministries/Departments and other stake holders in proper implementation of these provisions, a need has been felt to consolidate these provisions and place the same in the public domain for easy access as and when required. Accordingly, the relevant provisions of the Act/Rules/executive instructions have been compiled as under:

(A) DEFINITION OF "SEXUAL HARASSMENT" AND "WORKPLACE"

Section 2(n) and 2(o) of the SHWW (PPR) Act defines "Sexual Harassment" and "Workplace" respectively. The same have been incorporated through an amendment in the CCS (Conduct) Rules, 1964 as under:

"Rule 3C - Prohibition of sexual harassment of working women

- (1) No Government servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at any work place.*
- (2) Every Government servant who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.*

Explanation- 1 For the purpose of this rule,

(a) "sexual harassment" includes any one or more of the following acts or behaviour, (whether directly or by implication), namely:—

- (i) physical contact and advances; or*
- (ii) demand or request for sexual favours; or*
- (iii) sexually coloured remarks; or*
- (iv) showing any pornography; or*
- (v) any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of a sexual nature.*

(b) The following circumstances, among other circumstances, if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behaviour of sexual harassment may amount to sexual harassment: -

- (i) implied or explicit promise of preferential treatment in employment; or*
- (ii) implied or explicit threat of detrimental treatment in employment; or*
- (iii) implied or explicit threat about her present or future employment status; or*
- (iv) interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her; or*
- (v) humiliating treatment likely to affect her health or safety.*

(c) "workplace" includes, -

- (i) any department, organisation, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the Central Government;*
- (ii) hospitals or nursing homes;*
- (iii) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto;*

- (iv) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey;
- (v) a dwelling place or a house."

(Rule 3-C of the CCS (Conduct) Rules, 1964)

(B) COMPLAINTS COMMITTEE:

- ❖ Complaints Committees have been set up in all Ministries/Department and organizations under them in pursuance to the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the *Vishakha* case. As per Section 4(1) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 ("the Act"), the Internal Complaints Committee (referred to as "Complaints Committee" hereafter) is to be set up at every workplace. As per Section 4(2), this will be headed by a woman and at least half of its members should be women. In case a woman officer of sufficiently senior level is not available in a particular office, an officer from another office may be so appointed. To prevent the possibility of any undue pressure or influence from senior levels, such Complaints Committees should involve a third party, either an NGO or some other body which is familiar with the issue of sexual harassment.

[Para 1 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

❖ Section 4 of the SHWW (PPR) Act-

"4. Constitution of Internal Complaints Committee.— (1) Every employer of a workplace shall, by an order in writing, constitute a Committee to be known as the "Internal Complaints Committee":

Provided that where the offices or administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the Internal Committee shall be constituted at all administrative units or offices.

(2) The Internal Committees shall consist of the following members to be nominated by the employer, namely: —

(a) a Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at workplace from amongst the employees:

Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace referred to in sub-section(1):

Provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level woman employee, the Presiding Officer shall be nominated from any other workplace of the same employer or other department or organisation;

(b) not less than two Members from amongst employees preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have legal knowledge;

(c) one member from amongst non-governmental organisations or associations committed to the cause of women or a person familiar with the issues relating to sexual harassment:

(3) The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years, from the date of their nomination as may be specified by the employer.

(4) The Member appointed from amongst the non-governmental organisations or associations shall be paid such fees or allowances for holding the proceedings of the Internal Committee, by the employer, as may be prescribed.

(5) Where the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee, —

(a) contravenes the provisions of section 16; or

(b) has been convicted for an offence or an inquiry into an offence under any law for the time being in force is pending against him; or

(c) he has been found guilty in any disciplinary proceedings or a disciplinary proceeding is pending against him; or

(d) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest,

such Presiding Officer or Member, as the case may be, shall be removed from the Committee and the vacancy so created or any casual vacancy shall be filled by fresh nomination in accordance with the provisions of this section."

[Section 4 of the SHWW (PPR) Act]

❖ **Seniority of the Chairperson of the Complaint Committee-**

There is no bar either in the CCS (CCA) Rules or under the *Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013* to the Chairperson of the Complaints Committee being junior to the suspect officer or the charged officer. Hon'ble Allahabad High Court has in *Smt. Shobha Goswami vs State of U.P. and 2 Ors*, in WRIT – A No. – 31659 of 2015 observed as follows:

"In my opinion, there is nothing in the Scheme of the section which requires the lady member to be senior in rank to the officer against whom the allegation of sexual harassment are brought. The language of Section 4 of the Act only requires the lady member to the Senior Level".

This also does not in any way cause any prejudice to the charged officer.

[Para 2 of OM No. 11013/2/2014-Estt.A-III dated 09.09.2016]

❖ **Complaints Committee to be Inquiring Authority**

As per Proviso to Rule 14(2) of CCS (CCA) Rules, 1965, in case of complaints of sexual harassment, the Complaints Committee set up in each Ministry or Department etc. for inquiring into such complaints shall be deemed to be the Inquiring Authority appointed by the Disciplinary Authority for the purpose of these rules. Complaints Committee, unless a separate procedure has been prescribed, shall hold the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in the Rule 14.

[Para 6 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

❖ **Proviso to Rule 14(2) of the CCS (CCA) Rules, 1965-**

"Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3 C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Ministry or Department or Office for inquiring into such complaints, shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority for the purpose of these rules and the Complaints Committee shall hold, if separate procedure has not been prescribed for the Complaints Committee for holding the inquiry into the complaints of sexual harassment, the inquiry as far as practicable in accordance with the procedure laid down in these rules."

[Proviso to Rule 14(2) of the CCS (CCA) Rules, 1965]

(C) INQUIRY INTO COMPLAINTS [FIRST STAGE]

- The Complaints Committees may act on complaints of sexual harassment when they receive them directly or through administrative authorities etc, or when they take cognizance of the same suo-moto. As per **Section 9 (1) of the Act**, the aggrieved woman or complainant is required to make a complaint within three months of the incident and in case there has been a series of incidents, three months of the last incident. The Complaints Committee may however extend the time limit for reasons to be recorded in writing, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the complainant from filing a complaint within the stipulated period.
- As mentioned above, the complaints of sexual harassment are required to be handled by Complaints Committee. On receipt of a complaint, facts of the allegation are required to be verified. This is called preliminary enquiry/fact finding enquiry or investigation. The Complaints Committee conducts the investigation. They may then try to ascertain the truth of the allegations by collecting the documentary evidence as well as recording statements of any possible witnesses including the complainant. If it becomes necessary to issue a Charge Sheet, disciplinary authority relies on the investigation for drafting the imputations, as well as for evidence

by which the charges are to be proved. Therefore this is a very important part of the investigation.

[Para 7 and 8 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

➤ **Section 9 of the the SHWW (PPR) Act**

"9. Complaint of sexual harassment.— (1) Any aggrieved woman may make, in writing, a complaint of sexual harassment at workplace to the Internal Committee if so constituted, or the Local Committee, in case it is not so constituted, within a period of three months from the date of incident and in case of a series of incidents, within a period of three months from the date of last incident:

Provided that where such complaint cannot be made in writing, the Presiding Officer or any Member of the Internal Committee or the Chairperson or any Member of the Local Committee, as the case may be, shall render all reasonable assistance to the woman for making the complaint in writing:

Provided further that the Internal Committee or, as the case may be, the Local Committee may, for the reasons to be recorded in writing, extend the time limit not exceeding three months, if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the woman from filing a complaint within the said period.

(2) Where the aggrieved woman is unable to make a complaint on account of her physical or mental incapacity or death or otherwise, her legal heir or such other person as may be prescribed may make a complaint under this section."

[Section 9 of the SHWW (PPR) Act]

➤ **Rule 6 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013**

"6. Complainant of Sexual Harassment.- For the purpose of sub-Section (2) of Section 9,-

(i) Where the aggrieved women is unable to make a complaint on account of her physical incapacity, a complaint may be filed by –

(a) her relative or friend; or

(b) her co-worker; or

(c) an officer of the National Commission for Women or State Women's Commission; or

(d) any person who has knowledge of the incident, with the written consent of the aggrieved women;

(ii) where the aggrieved women is unable to make a complaint on account of her mental incapacity, a complaint may be filed by-

(a) her relative or friend; or

- (b) a special educator; or
- (c) a qualified psychiatrist or psychologist; or
- (d) the guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care; or
- (e) any person who has knowledge of the incident jointly with her relative or friend or a special educator or qualified psychiatrist or psychologist, or guardian or authority under whose care she is receiving treatment or care;

(iii) where the aggrieved woman for any other reason is unable to make a complaint, a complaint may be filed by any person who has knowledge of the incident, with her written consent;

(iv) where the aggrieved woman is dead, a complaint may be filed by any person who has knowledge of the incident, with the written consent of her legal heir."

➤ **Section 11 of the SHWW (PPR) Act**

"11. Inquiry into complaint.— (1) Subject to the provisions of section 10, the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall, where the respondent is an employee, proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent and where no such rules exist, in such manner as may be prescribed or in case of a domestic worker, the Local Committee shall, if prima facie case exist, forward the complaint to the police, within a period of seven days for registering the case under section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), and any other relevant provisions of the said Code where applicable:

Provided that where the aggrieved woman informs the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, that any term or condition of the settlement arrived at under sub-section (2) of section 10 has not been complied with by the respondent, the Internal Committee or the Local Committee shall proceed to make an inquiry into the complaint or, as the case may be, forward the complaint to the police:

Provided further that where both the parties are employees, the parties shall, during the course of inquiry, be given an opportunity of being heard and a copy of the findings shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the findings before the Committee.

(2) Notwithstanding anything contained in section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the court may, when the respondent is convicted of the offence, order payment of such sums as it may consider appropriate, to the aggrieved woman by the respondent, having regard to the provisions of section 15.

(3) For the purpose of making an inquiry under sub-section (1), the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall have the same powers as are vested in a civil court the Code of Civil

Procedure, 1908 (5 of 1908) when trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;*
- (b) requiring the discovery and production of documents; and*
- (c) any other matter which may be prescribed.*

(4) The inquiry under sub-section (1) shall be completed within a period of ninety days."

➤ **Rule 7 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013**

"7. Manner of Inquiry into complaint.- (1) Subject to the provisions of section 11, at the time of filing the complaint, the complainant shall submit to the Complaints Committee, six copies of the complaint along with supporting documents and the names and addresses of the witness.

(2) On receipt of the complaint, the Complaints Committee shall send one of the copies received from the aggrieved woman under sub-rule(1) to the respondent within a period of seven working days.

(3) The respondent shall file his reply to the complaint along with his list of documents, and names and addresses of witnesses within a period not exceeding ten working days from the date of receipt of the documents specified under sub-rule(1).

(4) The Complaints Committee shall make inquiry into the complaint accordance with the principles of natural justice.

(5) The Complaints Committee shall have the right to terminate the inquiry proceedings or to give an ex parte decision on the complaint, if the complainant or respondent fails, without sufficient cause, to present herself or himself for three consecutive hearings convened by the Chairperson or Presiding Officer, as the case may be:

Provided that such termination or ex-parte order may not be passed without giving a notice in writing, fifteen days in advance, to the party concerned.

(6) The parties shall not be allowed to bring in any legal practitioner to represent them in their case at any stage of the proceedings before the Complaints Committee.

(7) In conducting the inquiry, a minimum of three Members of the Complaints Committee including the Presiding Officer or the Chairperson, as the case may be, shall be present."

- On the completion of an inquiry under this Act, the Complaints Committee shall provide a report of its findings to the employer within a period of ten

days from the date of completion of the inquiry and such report be made available to the concerned parties.

[Section 13(1) of the SHWW (PPR) Act]

- Where the Complaints Committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has not been proved, it shall recommend to the employer that no action is required to be taken in the matter.

[Section 13(2) of the SHWW (PPR) Act]

- Where the Complaints Committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the employer to take action for sexual harassment as a misconduct in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent.

[Section 13(3)(i) of the SHWW (PPR) Act]

(D) INQUIRY UNDER CCS (CCA) RULES, 1965 [SECOND STAGE]

■ Dual Role

- In the light of the Proviso to the Rule 14 (2) mentioned above, the Complaints Committee would normally be involved at two stages. The first stage is investigation already discussed in the preceding para. The second stage is when they act as Inquiring Authority. It is necessary that the two roles are clearly understood and the inquiry is conducted as far as practicable as per Rule 14 of CCS (CCA) Rules, 1965. Failure to observe the procedure may result in the inquiry getting vitiated.
- As the Complaints Committees also act as Inquiring Authority in terms of Rule 14(2) mentioned above, care has to be taken that at the investigation stage that impartiality is maintained. Any failure on this account may invite allegations of bias when conducting the inquiry and may result in the inquiry getting vitiated. As per the instructions, when allegations of bias are received against an Inquiring Authority, such Inquiring Authority is required to stay the inquiry till the Disciplinary Authority takes a decision on the allegations of bias. Further, if allegations of bias are established against one member of the Committee on this basis, that Committee may not be allowed to conduct the inquiry.
- In view of the above, the Complaints Committee when investigating the allegations should make recommendations on whether there is a prima facie substance in the allegations which calls for conducting a formal inquiry. They should avoid making any judgmental recommendations or expressing views which may be construed to have prejudiced their views while conducting such inquiry.

[Para 9 to 11 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ Decision to issue Charge sheet. and conducting Inquiry

- On receipt of the Investigation Report, the Disciplinary Authority should examine the report with a view to see as to whether a formal Charge Sheet needs to be issued to the Charged Officer. As per Rule 14(3), Charge Sheet is to be drawn by or on behalf of the Disciplinary Authority. In case the Disciplinary Authority decides on that course, the Charged Officer should be given an opportunity of replying to the Charge sheet. As per Rule 14 (5), a decision on conducting the inquiry has to be taken after consideration of the reply of the charged officer.
- If the Charged Officer admits the charges clearly and unconditionally, there will be no need for a formal inquiry against him and further action may be taken as per Rule 15 of the CCS (CCA) Rules.

[Para 12 and 13 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ The Inquiry-stages

- In case the Charged Officer denies the charges and his reply is not convincing, the Charge sheet along with his reply may be sent to the Complaints Committee for formal inquiry, and documents mentioned in Rule 14 (6) will be forwarded to the Complaints Committee. As per Section 11(3) of the Act, for the purpose of making an inquiry, the Complaints Committee shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 when trying a suit in respect of the following matters, namely:—
 - (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
 - (b) requiring the discovery and production of documents; and
 - (c) any other matter which may be prescribed.
- The Disciplinary Authority shall also in terms of Rule 14(5)(c) appoint a Government servant as a Presenting Officer to present evidence on behalf of prosecution before the Complaints Committee/ Inquiring Authority. The listed documents are to be sent to the Presenting Officer. The Complaints Committee would, thereafter, summon the Presenting Officer and the Charged Officer. As a first step, the charged officer would be formally asked as to whether he admits the charges. As mentioned above, in case of any clear and unconditional admission of any Article of Charge, no inquiry would be held in respect of that Article and the admission of the Charged Officer would be taken on record. The inquiry would be held, thereafter, in respect of those charges which have not been admitted by the Charged Officer. The Charged Officer is also entitled to engage a Defence Assistant. The provisions relating to Defence Assistant are given in Rule 14(8).

- A
- The Inquiring Authority is, thereafter, required to ask the Presenting Officer to have the prosecution documents, listed in the Charge Sheet inspected by the Charged Officer. Copies of such documents, if not only given to the Charged Officer, would be handed over to him. The Charged Officer would, therefore, be required to submit a list of documents and witnesses which he wants to produce in support of his defense. The Inquiring Authority would consider allowing such documents or witnesses on the basis of their relevance. Normally, any document or witness which reasonably appears to be relevant and helpful in defense may be allowed. Once the documents have been allowed, the Inquiring Authority would send a requisition for these documents to the custodian of such documents.
 - When the regular hearing commences, the Inquiring Authority would ask the Presenting Officer to produce the documentary evidence. Such documents as are disputed by the Charged Officer have to be proved by the witnesses before they are taken on record. The undisputed documents would be taken on record and marked as exhibits.

[Para 14 to 17 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ **Examination of Witnesses**

- Summons would, thereafter, be sent to the witnesses listed in the Charge sheet. The Presenting Officer may choose to produce them in any order he finds appropriate. These witnesses would be examined in the inquiry in the following manner. The examination in chief would be done by the Presenting Officer where the Presenting Officer may ask questions of the witness to ascertain the facts. The witness would, thereafter, be cross-examined by the Defense. After the cross-examination, the Presenting Officer would be given an opportunity to re-examine the witness. In the examination in chief, leading questions are not allowed. These are however allowed in the cross examination.
- The procedure of Inquiry requires opportunity to the Charged Officer to cross-examine all the witnesses that appear on behalf of the Prosecution. Failure to do so may be construed as a denial of reasonable opportunity to the charged officer, resulting in vitiation of the Inquiry. If the complainant appears as a witness, she would also be examined and cross-examined. The Inquiry Officer may however disallow any questions which are offensive, indecent or annoying to the witnesses, including the complainant.
- If Inquiring Authority wishes to ascertain some facts for clarity, he may pose questions to the witnesses. This should however, be done in such a manner as to not show any bias for or against the Charged Officer. This has to be done in the presence of the Presenting Officer and the Charged Officer/Defence Assistant. No

inquiry should be conducted behind the back of the charged officer. The witnesses will be examined one by one, and the other witness who are either yet to be examined, or have been examined are not allowed to be present during the examination of a witness.

[Para 18 to 20 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ **Daily Order Sheet**

The Inquiring Authority would also maintain a document called Daily Order Sheet in which all the main events of the inquiry and including requests/representations by the Charged Officer or the Presenting Officer, and decisions thereon would be recorded. For example (i) if the Charged Officer refuses to cross-examine the witnesses, this should be recorded in the Daily Order Sheet (ii) the Daily Order Sheet should record that the Charged Officer had been advised that he has the right to engage a Defense Assistant (iii) it should also be clearly mentioned that the Charged Officer was also informed as to who are eligible to assist him as Defense Assistant. (iv) the Daily Order Sheet should also record in case request of the Charged Officer for engaging a particular person as Defense Assistant is disallowed in the light of the existing instructions. Daily Order Sheet should be signed by the Inquiring Authority, Presenting Officer and the Charged Officer/Defence Assistant.

[Para 21 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ **Defence Evidence**

After the prosecution evidence is over, the Charged Officer is required to submit his statement of defense. In this statement, the Charged Officer is required to briefly indicate his line of defense. After this, the Defense evidence will be taken. The evidence will be produced in the same order as the prosecution evidence. First, the documents allowed by the Inquiry Authority would be taken on record and then the witnesses called and their examination, cross-examination and re-examination done. The only difference here would be that the Examination in Chief would be done by defense while the cross-examination would be done by the prosecution. The defense would then have the opportunity of re-examining the witness.

[Para 22 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ **General Examination of the Charged Officer**

After the Defense evidence is over, the Inquiring Authority shall ask Charged Officer as to whether he wishes to appear as his own witness. In case he does so, he will be examined like any other defense witness. In case however, he declines to do so, the Inquiring Authority is required to generally question him. At this stage due care is required to be exercised that as per Rule 14(18)

the purpose of this stage is to apprise Charged Officer of the circumstances which appear to be against him. This is to enable the Charged Officer to explain them to the Inquiring Authority. Presenting Officer and the Defence Assistant do not take any part in the General Examination. Charged Officer may not be compelled to answer questions during examination by the Inquiring Authority.

[Para 23 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ **Brief**

- After this, the Presenting Officer would be asked to submit his brief. A copy of this brief would be given to the Charged Officer. Both the Presenting Officer and the Charged Officer may be allowed reasonable time for submission of their brief.
- The Inquiring Authority then writes the Inquiry Report in which the evidence in support of the charges and against them will be examined. The Report should be a speaking one clearly bringing out as to the evidence on the basis of which any particular conclusion has been reached. Based on this analysis, the Inquiring Authority will give its findings on the Articles as proved or not proved. In case any Article of charge is proved only partially, then the Inquiring Authority should record the extent to which that Article has been proved.

[Para 24 and 25 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ **Powers of the Committee to make recommendations**

- Normally, the Inquiry Officer is not allowed to make any recommendations in his report. Here the function of the Complaints Committee acting as the Inquiring Authority differs.

The Complaints Committee will also have the powers to recommend:-

- (a) to transfer the aggrieved woman or the charged officer to any other workplace; or
- (b) to grant leave to the aggrieved woman up to a period of three months. (The leave will not be deducted from her leave account).
- (c) to grant such other relief to the aggrieved woman as may be prescribed; or
- (d) to deduct from the salary or wages of the charged officer such sum as it may consider appropriate to be paid to the aggrieved woman or to her legal heirs. Any amount outstanding at the time of cessation of the services of the charged officer due to retirement, death or otherwise may be recovered from the

terminal benefits payable to the officer or his heirs. Such compensation will not amount to penalty under Rule 11 of CCS (CCA) Rules in terms of the Explanation (ix) to Rule 11.

- (e) to take action against complainant, if the allegation is malicious, or the complainant knows it to be false, or has produced any forged or misleading document.
- (f) to take action against any witness if such witness has given false evidence or produced any forged or misleading document.

[Para 6 and 7 of the OM No. 11013/2/2014-Estt.A-III dated 27.11.2014]

[Para 5 and 26 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

- (g) The Complaints Committee at the written request of the aggrieved women may recommend to the employer to-
 - i. restrain the respondent from reporting on the work performance of the aggrieved women or written her confidential report, and assign the same to another officer;
 - ii. restrain the respondent in case of an educational institution from supervising any academic activity of the aggrieved women.

[Rule 8 of the SHWW (PPR) Rules, 2013]

- Rule 48 of CCS (Leave) Rules, 1972 [Special Leave connected with inquiry on sexual harassment]:

"48. Special Leave connected to inquiry of sexual harassment - Leave upto a period of 90 days may be granted to an aggrieved female Government Servant on the recommendation of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, during the pendency of inquiry under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the leave granted to the aggrieved female Government Servant under this rule shall not be debited against the leave account".

[Rule 48 of CCS (Leave) Rules, 1972]

- Explanation (ix) to Rule 11 of the CCS (CCA) Rules, 1965

"Explanation.—The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely:—

(ix) Any compensation awarded on the recommendation of the Complaints Committee referred to in the proviso to sub-rule (2) of rule 14 and established in the Department of the Government of India for inquiring into any complaint of

sexual harassment within the meaning of rule 3 C of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964'

■ **Prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings.—**

- The Complaints Committee should also remember that as per the Section 16 of the Act, notwithstanding the RTI Act, 2005, information as regards identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, Inquiry proceedings, Recommendations of the Committee, shall not be published or communicated or made known to public, press or media in any manner. Provided that information may be disseminated regarding the justice secured to any victim of sexual harassment under Act without disclosing the name, address, identity or any other particulars calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and witnesses.

[Para 27 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

➤ **Section 16 and 17 of the the SHWW (PPR) Act**

"16. Prohibition of publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings.—*Notwithstanding anything contained in the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the contents of the complaint made under section 9, the identity and addresses of the aggrieved woman, respondent and witnesses, any information relating to conciliation and inquiry proceedings, recommendations of the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, and the action taken by the employer or the District Officer under the provisions of this Act shall not be published, communicated or made known to the public, press and media in any manner:*

Provided that information may be disseminated regarding the justice secured to any victim of sexual harassment under this Act without disclosing the name, address, identity or any other particulars calculated to lead to the identification of the aggrieved woman and witnesses."

- **17. Penalty for publication or making known contents of complaint and inquiry proceedings.—***Where any person entrusted with the duty to handle or deal with the complaint, inquiry or any recommendations or action to be taken under the provisions of this Act, contravenes the provisions of section 16, he shall be liable for penalty in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist, in such manner as may be prescribed.*

- With the above stage, the inquiry would be formally over. The Inquiring Authority should prepare separate folders containing the documents mentioned in Rule 14(23)((ii) of CCS (CCA) Rules, 1965

[Para 28 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ Suspension of the Charged Officer

A Government servant may also be placed under suspension before or after issue of a Charge Sheet where his continuance in office will prejudice the investigation, for example if there is an apprehension that he may tamper with witnesses or documents. Suspension may also be resorted to where continuance of the Government servant in office will be against wider public interest such as there is a public scandal and it is necessary to place the Government servant under suspension to demonstrate the policy of the Government to deal strictly with officers involved in such scandals. It may be desirable to resort to suspension in case of misdemeanor involving acts of moral turpitude.

[Para 29 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

■ Transfer of Charged Officer:

To ensure fair inquiry, Ministries/ Departments may also consider transferring the suspect officer/ charged officer to another office to obviate any risk of that officer using the authority of his office to influence the proceedings of the Complaints Committee.

[Para 3 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 09.09.2016]

■ Special provisions to deal with threats or intimidation

Disciplinary Authority may also dispense with inquiry under Rule 19(ii), and action may be taken without the inquiry when the Disciplinary Authority concludes that it is not reasonably practicable to hold such an inquiry. The circumstances leading to such a conclusion may exist either before the inquiry is commenced or may develop in the course of the inquiry. Such situation would be deemed to have arisen:

- (i) where the Government servant, through or together with his associates terrorizes, threatens or intimidates witnesses who are likely to give evidence against him with fear of reprisal in order to prevent them from doing so; or
- (ii) where the Government servant himself or with or through others threatens, intimidates and terrorizes the Disciplinary Authority, Members of the Committee, the Presenting Officer or members of their family.

[Para 30 of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

- Disciplinary Authority is not expected to dispense with the inquiry lightly, arbitrarily or with ulterior motive or merely because the case against the Government servant is weak.

[Last Para of OM No. 11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16.07.2015]

(E) APPEAL UNDER SECTION 18(1) OF THE SHWW (PPR) ACT, 2013 BY THE COMPLAINANT

- Where a Complaint Committee has not recommended any action against the employee against whom the allegation have been made in a case of involving allegations of sexual harassment, the Disciplinary Authority shall supply a copy of the Report of the Complaints Committee to the complainant and shall consider her representation, if any submitted, before coming to a final conclusion. The representation shall be deemed to be an appeal under section 18(1) of the Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

[Para 3 of OM No. 11012/5/2016-Estt.A-III dated 02.08.2016]

- **Section 18 of the the SHWW (PPR) Act [Appeal]**

"18 Appeal.—(1) Any person aggrieved from the recommendations made under sub-section (2) of section 13 or under clause (i) or clause (ii) of sub-section (3) of section 13 or sub-section (1) or subsection (2) of section 14 or section 17 or non-implementation of such recommendations may prefer an appeal to the court or tribunal in accordance with the provisions of the service rules applicable to the said person or where no such service rules exist then, without prejudice to provisions contained in any other law for the time being in force, the person aggrieved may prefer an appeal in such manner as may be prescribed.

(2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of ninety days of the recommendations."

(F) Sexual Harassment electronic-Box (She-Box)

- Ministry of Women & Child Development launched an online complaint management system titled Sexual Harassment electronic-Box (She-Box) on 24th July, 2017 for registering complaints related to sexual harassment at workplace. The She-Box is an initiative to provide a platform to the women working or visiting any office of Central Government (Central Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies and Institutions etc.) to file complaints related to sexual harassment at workplace under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.
- Once a complaint is submitted to She-Box, it will be directly sent to the Internal Complaint Committee (ICC) of the concerned Ministry/ Department/ PSU/ Autonomous Body etc. having jurisdiction to inquire into the complaint. The She-Box also provides an opportunity to both the complainant and nodal administrative authority to monitor the

progress of inquiry conducted by the ICCs. The She-Box portal can be accessed at the link given below:

<http://www.shebox.nic.in/>

➤ Features of the She-Box are as under:

- (i) She-Box is an online Complaint Management System for lodging complaints related to sexual harassment of women at workplace. The steps required for filing of complaint through She-Box can be downloaded from the link: <http://www.shebox.nic.in/assets/site/downloads/manual.pdf>
- (ii) Any woman working or visiting any office of Central Government (Central Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies and Institutions etc.) can file complaint related to sexual harassment at workplace through this She-Box.
- (iii) Once a complaint is submitted to the She-Box, it will directly send the complaint to the Internal Complaints Committee (ICC) of the concerned Ministry/ Department/ PSU/ Autonomous Body etc. having jurisdiction to inquire into the complaint. The Internal Complaints Committee will take action as prescribed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and update the status of the complaint through '**Administrator Login**'.
- (iv) The status of complaint can be viewed at any time by pressing the tab '**View Status of Your Complaint**' within She-Box.

➤ The complaint registered in the She-Box contains only a brief description of the incident of sexual harassment at workplace. The Internal Complaints Committee (ICC) is required to initiate inquiry as prescribed under Section 11 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 read with Department of Personnel & Training's O.M. No.11013/2/2014-Estt.(A-III) dated 16th July, 2015 by calling upon the complainant to provide detailed complaint along with all the relevant evidences (documentary or otherwise).

(G) Duties of the employer:-

➤ **Rule 3C(2) of the CCS (Conduct) Rules, 1964**

Every Government servant who is incharge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at the work place.

➤ **Section 19 of the the SHWW (PPR) Act [Duties of employer]**

"19. Duties of employer.— Every employer shall—

- (a) provide a safe working environment at the workplace which shall include safety from the persons coming into contact at the workplace;*
- (b) display at any conspicuous place in the workplace, the penal consequences of sexual harassments; and the order constituting, the Internal Committee under sub-section (1) of section 4;*
- (c) organise workshops and awareness programmes at regular intervals for sensitising the employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the members of the Internal Committee in the manner as may be prescribed;*
- (d) provide necessary facilities to the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, for dealing with the complaint and conducting an inquiry;*
- (e) assist in securing the attendance of respondent and witnesses before the Internal Committee or the Local Committee, as the case may be;*
- (f) make available such information to the Internal Committee or the Local Committee, as the case be, as it may require having regard to the complaint made under sub-section (1) of section 9;*
- (g) provide assistance to the woman if she so chooses to file a complaint in relation to the offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force;*
- (h) cause to initiate action, under the Indian Penal Code (45 of 1860) or any other law for the time being in force, against the perpetrator, or if the aggrieved woman so desires, where the perpetrator is not an employee, in the workplace at which the incident of sexual harassment took place;*
- (i) treat sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate action for such misconduct;*
- (j) monitor the timely submission of reports by the Internal Committee"*

[Section 19 of the SHWW (PPR) Act]

- It should be ensured that Complaints Committee shall at all time be in existence and changes in its composition, whenever necessary, should be made promptly and adequately publicized. The composition of the Complaint Committee should also be posted on the website of the concerned Ministries/ Departments/ Office concerned. It would also be desirable for the Committees to meet once a quarter, even if there is no live case, and review preparedness to fulfil all requirements of the Vishakha judgment in the Department/ Ministry/ organization concerned.

[OM No. 11013/2/2014-Estt.A-III dated 02.02.2015]

- It should be ensured that the aggrieved women are not victimized in connection with the complaints filed by them. For a period of five years after a decision in a proven case of sexual harassment, a watch should be kept to

ensure that she is not subjected to vendetta. She should not be posted under the Respondent, or any other person where there may be a reasonable ground to believe that she may be subjected to harassment on this account. In case of any victimization the complainant may submit a representation to the Secretary in the case of Ministries/Departments and Head of the Organization in other cases. These representations should be dealt with sensitivity, in consultation with the Complaints Committee, Ministries/Department and Head of the Organization in other cases. These representations should be dealt with sensitivity, in consultation with the Complaints Committee, and a decision taken within 15 days of the submission of the same.

[Para 3 of the OM No 11013/7/2016-Estt.A-III dated 22.12.2016]

- All Ministries/Department shall furnish a **monthly report** to the Ministry of Women and Child Development giving details of number of complaints received, disposed of and action taken in the case.

[Para 4 of the OM No 11013/7/2016-Estt.A-III dated 22.12.2016]

(H) Provisions regarding preparation of Annual Report by Complaints Committee

- **Section 21 of the the SHWW (PPR) Act**

"21. Committee to submit annual report.— (1) The Internal Committee or the Local Committee, as the case may be, shall in each calendar year prepare, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report and submit the same to the employer and the District Officer.

(2) The District Officer shall forward a brief report on the annual reports received under sub-section (1) to the State Government."

- **Rule 14 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013**

"14. Preparation of annual report.- The annual report which the Complainants Committee shall prepare under Section 21, shall have the following details:-

- (a) number of complaints of sexual harassment received in the year;*
- (b) number of complaints disposed off during the year;*
- (c) number of cases pending for more than ninety days;*
- (d) number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out;*
- (e) nature of action taken by the employer or District Officers."*

(I) **Provisions regarding preparation of Annual Report by Employer**

- Attention of all Ministries is invited to Section 22 of the Act relating to including information in Annual Report, and to request that information relating to number of cases filed, if any, and their disposal may be included in the Annual Report of the Ministry/ Department.

[Para 6 of the OM No. 11013/2/2014-Estt.A-III dated 02.02.2015]

➤ **Section 22 of the the SHWW (PPR) Act**

"22. Employer to include information in annual report.—The employer shall include in its report the number of cases filed, if any, and their disposal under this Act in the annual report of his organisation or where no such report is required to be prepared, intimate such number of cases, if any, to the District Officer"

(J) **Miscellaneous-**

- Fees or allowance for Member of the Complaints Committee is mentioned in Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition or Redressal) Rules, 2013

Note: List of the OMs mentioned in this document is **annexed**. In case any reference to the relevant OM is required, the same may be accessed by clicking on the hyperlink or from the DOPT's website.

ANNEXURE

List of Rules, Notifications and OMs mentioned in this Document

Acts and Rules		
No.		
1.	Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	
2.	Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules, 2013	
3.	Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965	
4.	Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964	
5.	Central Civil Services (Leave) Rules, 1972	
S. No.	OM No.	Subject
1.	OM.No.11013/10/97-Estt.A dated 13.02.1998	CCS(Conduct) Rules, 1964 – Supreme Court Judgment in the case of Vishaka Vs. State of Rajasthan regarding sexual harassment of working women.
2.	OM.No.11013/10/97-Estt.A dated 13.07.1999	Prevention of sexual harassment of working women – Supreme Court judgment in the case of Vishaka Vs. State of Rajasthan.
3.	OM.No.11013/11/2001-Estt.A dated 12.12.2002	Report of the Complaints Committee constituted for prevention of sexual harassment of women at work places – follow up action.
4.	OM.No.11013/11/2001-Estt.A dated 04.08.2005	Report of the Complaints Committee constituted for prevention of sexual harassment of women at work places – follow up action.
5.	OM.No.11013/3/2009-Estt.A dated 2.2.2009	CCS(Conduct) Rules, 1964 – constitution of a Complaints Committee to enquire into complaints of sexual harassment made against officers of the level of Secretary and Additional Secretary to the Government of India.
6.	OM.No.11013/3/2009-Estt.A dated 21.7.2009	CCS(Conduct) Rules, 1964 – Guidelines regarding prevention of sexual harassment of working women in the workplace.
7.	OM.No.11013/3/2009-Estt.A dated 3.8.2009	CCS(Conduct) Rules, 1964 – Guidelines regarding prevention of sexual harassment of working women in the workplace.
8.	OM.No.11013/3/2009-Estt.A dated 7.8.2009	CCS(Conduct) Rules, 1964 – Guidelines regarding prevention of sexual harassment of working women in the workplace.
9.	OM.No.11013/3/2009-Estt.A dated 8.10.2009	Complaints Committee mechanism relating to sexual harassment.
10.	OM.No.11013/2/2014-Estt.A-III dated 27.11.2014	Alignment of Service Rules with the Sexual Harassment of women at workplace (prevention, prohibition and redressal) Act 2013.
11.	OM.No.11013/2/2014-Estt.A-III dated 2.2.2015	CCS(Conduct) Rules 1964 – Guidelines regarding prevention of sexual harassment of women at the

		workplace – regarding.
12.	OM.No.11013/2/2014-Estt.A-III dated 5.5.2015	Meeting held on 16.04.2015 to review the progress of implementation of the guidelines on prevention of sexual harassment of women at the workplace – forwarding of Minutes – reg.
13.	OM.No.11013/2/2014-Estt.A-III dated 16.7.2015	Steps for conducting inquiry in case of allegation of Sexual Harassment.
14.	OM.No.11013/2/2014-Estt.A-III dated 30.7.2015	Steps for conducting inquiry in case of allegation of Sexual Harassment.
15.	OM.No.13026/2/2016-Estt.L dated 14.7.2016	Implementation of leave provision under the sexual harassment of women at workplace (prevention, prohibition & redressal) Act, 2013 – reg.
16.	OM.No.11012/5/2016Estt.A-III dated 2.8.2016	CCS(CCA) Rules, 1965 – Guidelines regarding prevention of sexual harassment of women at the workplace – reg.
17.	OM.No.11013/2/2014-Estt.A-III dated 9.9.2016	Prevention of Sexual Harassment of working women at workplace - Seniority of the Chairperson of the Complaint Committee – reg.
18.	OM.No.11013/7/2016-Estt.A-III dated 22.12.2016	CCS(Conduct) Rules, 1961 – Guidelines regarding prevention of sexual harassment of women at the workplace – reg.
19.	OM.No.11013/7/2016-Estt.A-III dated 1.11.2017	Online complaint management system titled “Sexual Harassment electronic-Box (She-Box)” – reg.